



एग्री आर्टिकल्स

(कृषि लेखों के लिए ई-पत्रिका)

वर्ष: 03, अंक: 05 (सितम्बर-अक्टूबर, 2023)

www.agriarticles.com पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री आर्टिकल्स, आई. एस. एन.: 2582-9882

किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण में, किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) एक बेहतर विकल्प

(*शैलू यादव, डॉ. अभिषेक शर्मा एवं आशीष यादव)

मृदा विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश

*संवादी लेखक का ईमेल पता: shailuyadav0512@gmail.com

किसान उत्पादक संगठन एक प्रकार का किसान-सदस्यो द्वारा नियंत्रित स्वैच्छिक संगठन या किसानों का एक समूह है, किसान अपने संगठन का कोई नाम रखकर उसे कम्पनी एक्ट 2013 के माध्यम से पंजीकृत कराते हैं। जिससे किसानों को वे सभी फायदे मिलते हैं, जो एक कम्पनी को मिलते हैं। किसान उत्पादक संगठन के सदस्य इसकी नीतियों के निर्माण एवं निर्णय में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मुख्यतः एफ.पी.ओ. लघु एवं सीमान्त किसानों का एक समूह है, इससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज के लिए बाजार मिलता है, बल्कि खेत में लगने वाले खाद बीज, दवाईयो एवं कृषि यंत्रों की खरीद भी सस्ती पडती है। बाजार की सेवाएँ सीधे मिलने से किसानों को बिचौलियों के मकडजाल से मुक्ति मिलती है।

भारत सरकार द्वारा किसानों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने हेतु कई प्रयास किये जा रहे हैं, सरकार का लक्ष्य है, कि अधिक उत्पादन के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सकें। आज हमारे देश में कृषकों को कृषि उत्पादन से ज्यादा उसके विपणन के लिए बाजार में कठिनाईयो का सामना करना पडता है, देश में कुल किसानों में से 86 प्रतिशत छोटे और सीमान्त किसान हैं इस स्थिति को देखते हुए बड़े स्तर पर संरचनात्मक सुधार और परिवर्तन जैसी पहल को लेकर सरकार ने 2019-20 से लेकर 2023-24 तक 10,000 एफ.पी.ओ. बनाने की घोषणा की है। ऐसे किसान उत्पादक संगठन जो किसानों के हितों में 03 वर्ष तक लगातार कार्य करते हैं, उन उत्पादक संगठनों को सरकार 15 लाख रु की आर्थिक सहायता एफ.पी.ओ. योजना के तहत उपलब्ध कराती है, जो कि किसानों को उनकी खेती के खर्चों से निपटने के लिए दी जाती है जैसे खेती की तैयारी, बीजों की खरीदी, सिंचाई व्यवस्था और कृषि उपकरणों से खाद, उर्वरक, कीटनाशक तक के सभी खर्च शामिल है।

संगठन की आवश्यकता क्यों

सदस्यों के स्वामित्व वाले उत्पादक संगठनों या एफपीओ में किसानों को संगठित करने का प्राथमिक उद्देश्य देश में किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के उत्पादन, उनकी उत्पादक क्षमता एवं लाभ में वृद्धि करना है। छोटे किसानों को सरकारी सहायता आदि इस तरह से नहीं मिल पाती है जैसे की बड़े किसानों को, इस उद्देश्य से कि किसानों की हर संभव मदद प्रदान की जा सके एवं, भारतीय कृषि विपणन में जो दलालों की एक लम्बी चैन है, जो बिल्कुल भी पारदर्शी तरीके से काम नहीं करती है जिसकी वजह से किसानों को उनके उत्पादों का बहुत कम दाम मिल पाता है, उससे छुटकारा दिलाया जा सके। इसके साथ ही उपभोक्ता जितना पैसा उस उत्पाद के लिए देता है उसका अधिकतम हिस्सा किसानों तक पहुच पाये एवं संगठन की ताकत से किसान अपने उपज को ज्यादा मूल्य पर बेच पाने में समक्ष हो सके। बाजार की मुख्य धारा में किसान को लाना, बाजार आधारित कृषि पर जोर एवं उत्पादन की लागत को कम कर, उत्पादन बढ़ाना छोटे एवं लघु किसान उद्यमियों को शासकीय योजनाओं से जोडना।

किसान उत्पादक संगठन का संचालन

किसान उत्पादक संगठन का संचालन त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित है, केन्द्र सरकार के किसान कल्याण एवं कृषि मंत्रालय द्वारा लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी) को नोडल एंजेंसी के रूप में एफ.पी.ओ. की विभिन्न परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारें एवं अन्य एजेंसियाँ इसके अन्तर्गत कई कार्यक्रम चला रही हैं। एफ.पी.ओ. के गठन और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए अभी एस.एफ.ए.सी. और नाबार्ड मिल कर कार्य कर रही थी, परन्तु अब सरकार इसे और बढ़ाना चाहती है जिसके लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी) के अन्तर्गत किसान उत्पादक संगठन परियोजना का निष्पादन और निरीक्षण एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एन.पी.एम.ए.) द्वारा किया जाता है।

आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए नाबार्ड किसान उत्पादक संगठनों की निगरानी करता है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसान उत्पादक संगठन के जरिये कितने किसानों को क्या फायदा पहुंच रहा है, बाजार में किसानों की पहुंच को किस प्रकार आसान बनाया जा रहा है, कागजी कार्यों को किस प्रकार निपटाया जाता है, किसानों को सस्ती दरों पर समान उपलब्ध हो रहा है या नहीं इन सभी बातों पर अमल करके किसान उत्पादक संगठनों को रेटिंग प्रदान की जाती है, जिसके बाद किसान उत्पादक संगठनों के पास सरकार द्वारा जारी आर्थिक अनुदान पहुंचना शुरू होता है।

किसान उत्पादक संगठन सम्बंधी महत्वपूर्ण नियम

उत्पादक कंपनी का गठन करने के लिए अपेक्षित उत्पादकों की न्यूनतम संख्या 10 है, जिसमें 05 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं 05 मेम्बर। जबकि सदस्यों की अधिकतम संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं है तथा संभाव्यता एवं आवश्यकता के अनुसार यह संख्या बढ़ाई जा सकती है। सभी प्रोड्यूसर होना चाहिए, यह सी.बी.बी.ओ. के तहत बनाया जाना चाहिए, राज्य एवं जिला स्तर पर इसे लागू करने के लिए एंजेंसी होनी चाहिए। इसे एक जिला एक उत्पाद के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए इसी के साथ विपणन, ब्रांडिंग, प्रोसेसिंग और निर्यात पर भी जोर देना चाहिए।

एफ.पी.ओ. बनाने से लाभ

- एफ.पी.ओ. किसानों को सामूहिक खेती के लिए प्रोत्साहित कर सकते, जिससे जोत के छोटे आकार से उत्पन्न उत्पादन से उत्पादकता संबंधी समस्याओं से किसानों को निजात मिल सकेगा।
- एफ.पी.ओ. किसानों को मोलभाव के दौरान बड़े उद्यमियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है क्योंकि यह सदस्यों को एक समूह के रूप में बातचीत एवं समझौता करने में सक्षम बनाता है।
- एफ.पी.ओ., सदस्य किसानों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण इनपुट उपलब्ध करा सकता है उदाहरण, फसलों के लिए ऋण, मशीनरी की खरीद, कृषि-इनपुट (उर्वरक कीटनाशक आदि)।
- इससे जुड़े किसानों को अपनी उपज के लिए बाजार मिलेगा, साथ ही उनके लिए खाद, बीज, दवाई, और कृषि उपकरण जैसा जरूरी सामान खरीदना बेहद आसान होगा।
- संगठन से किसानों को सौदेबाजी की शक्ति मिलती है।
- समूह में बहुलता से व्यापार करने पर, भण्डारण, परिवहन और प्रोसेसिंग के खर्चों में बचत होती है। समूह के किसान कस्टम केन्द्र आदि शुरू कर अपने व्यापार का विस्तार कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खतौनी (भूमि रिकॉर्ड)
- पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नम्बर

आवेदन प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन

देश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करना होगा।

- आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय कृषि बाजार की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.enam.gov.in/> पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा।
- होम पेज पर आपको एफ.पी.ओ. विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके समक्ष रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- आवेदन फॉर्म में चाही गई व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होगी
- इसके पश्चात आपको को पासबुक या फिर कौंसिल चेक एवं आईडी प्रूफ को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- अब आपको सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना होगा।

